विचार बिन्दु

जिस तरह घोंसला सोती हुई चिड़िया को आश्रय देता है उसी तरह मौन तुम्हारी वाणी को आश्रय देता है। –रवींद्रनाथ ठाकुर

चुनाव प्रचार अभियान में मोल-तोल के बोल दिखाएंगे अपना असर

समूचा देश अब चुनावमय हो गया है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी नित गठबंधन 400 पार का नारा बुलंद कर चुनाव अभियान को धार दे रही हैं तो दूसरी और विपक्षी गठबंधन इंडी भाजपा को सत्ताच्युत करने का लक्ष्य लेकर चुनाव अभियान को गति दे रहे हैं। पहले चरण के नामांकन का कार्य पूरा होने और दूसरे चरण के लिए नामांकन में तेजी के साथ ही अब चुनावी मोर्चे पर सभी दल जुट गए हैं। एक और तीसरी बार भी मोदी सरकार का लक्ष्य है तो दूसरी ओर विपक्ष मोदी सरकार को सत्ता से हटाने का लक्ष्य लेकर चुनावी जंग में आमने-सामने आ डटे हैं। दोनों ही पक्षों के पास जनता यानी कि मतदाता को अपने पक्ष करना और मतदाता का वोट अपने पक्ष में करने की बड़ी चुनौती है। अब चुनावी माहौल में सबसे बड़ी चुनौती मोल-तोल के बोल की हो गई है तो दूसरी ओर अपना पक्ष जनता के सामने रखने की हो गई है। एक बात साफ होनी चाहिए कि जनसभा या जनता से किसी भी माध्यम से संवाद की स्थिति में प्रचारकों द्वारा बोले गए एक एक शब्द का अर्थ होगा और विपक्षी पक्ष प्रचारक द्वारा बोले गए शब्दों का कहीं अपने अभियान का इक्के का पत्ता नहीं बना लें यह बड़ी चुनौती होगी। लोकसभा के पिछले दो चुनाव इसके उदाहरण है। जब नरेन्द्र मोदी पर की गई टिप्पणियां ही मोदी और भारतीय जनता पार्टी के लिए वरदान बन कर के सामने आई। इसलिए जनता के बीच बोलते समय काफी कुछ सोच-समझ कर बोलना होगा नहीं तो अर्थ का अनर्थ होने में देरी नहीं लगेगी।

राजनीतिक दलों के चुनाव अभियान के दौरान रैलियों, रोड शो सहित विभिन्न मंचों से एक दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी रहेगा। हाल ही पांच विधान सभा चुनावों के दौरान भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस, गारटियों की चर्चा ही रही। एक तरफ गांरटियां थी तो दूसरी और बीजेपी ने मोदी को ही गारंटी बताकर प्रचारित किया। दरअसल देखा जाएं तो पिछले कुछ चुनावों से चाहे वे लोकसभा के हो या विधानसभाओं के चुनाव हो, सीधे जनता से जुड़े मुद्दें तो कहीं नेपथ्य में ही रह जाते हैं। जनता से जुड़े मुद्दों को आम जनता भी अब मुद्दे या चुनावी एजेंडा नहीं मानने लगी है। किसी जमाने में गरीबी हटाओं या भ्रष्टाचार मिटाओं या महंगाई या बेरोजगारी तो सकारात्मक प्रचार अभियान में विकास की बात आदि मुद्दें महत्वपूर्ण होते थे पर पिछले चुनावों से यह मुद्दें वोट में बदल नहीं रहे हैं। दर असल अब नकारात्मक प्रचार का दौर चल पड़ा है और मजे की बात यह है कि यह नकारात्मक प्रचार उलटा पड़ने लगा है। पिछले दो लोकसभा के चुनावों में चौकीदार, सेना के साक्ष्य, चाय वाला आदि ऐसे वक्तव्य रहे जिसका जितना अधिक उपयोग हुआ वह भाजपा और नरेन्द्र मोदी के पक्ष में ही गया। विपक्ष के प्रयास है कि सत्तारुढ़ द्वारा संबैधानिक संस्थाओं यथा ईडी, आईटी आदि जांच एजेसिंयों का हथियार के रुप में उपयोग, चुनावी बॉण्ड, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार आदि को प्रभावी तरीके से चुनावी मुद्दा बनाया जाये पर यह मतदाताओं को प्रभावित करने वाले मुद्दे बन नहीं पा रहे हैं। इसका एक प्रमुख कारण तो विपक्षी खासतौर से इंडी के दलों का जुड़ना बिखरना जारी है। एक तरफ ममता पं.बगांल में कांग्रेस द्वारा वामपंथी दलों के साथ तालमेल कर चुनाव लड़ने को खुले आम भाजपा को लाभ बताने वाला निर्णय बता रही हैं वहीं बिहार, महाराष्ट्र, दिल्ली में कांग्रेस का छोटे पार्टनर के रुप में सामने आने, पंजाब में आप से सीटों के बंटवारें को लेकर समझौता ही नहीं होने, बसपा का अलग रुख, अजित जनता दल का बीजेपी के साथ आना, ओडीसा में बीजद सहित विरोधाभास सामने आ रहे हैं। वहीं दिल्ली की रैली में जो पैनापन दिखना चाहिए था वह पैनापन दिखाई नहीं दिया। चुनावी बॉण्ड का मुद्दा जिस तरह से उछला वह अपनी धार नहीं दिखा पाया क्योंकि चुनावी चंदा कम हो या ज्यादा लगभग सभी दलों ने लिया है। सभी राजनीतिक दल चुनावी चंदा लेते हैं और साफ है कि इसका फायदा सत्तारुढ़ दल को अधिक ही मिलता है।

रैलियों, सभाओं में प्रमुख नेताओं को भाषणों-वक्तव्यों के दौरान सावधानी बरतनी होगी तभी मोदी जी से पार पाया जा सकता है। मोदी जी विपक्षी नेताओं द्वारा कही गई बात को तत्काल अपने पक्ष में भुनाने में सिद्धहस्त है, ऐसे में विपक्ष के सामने प्रमुख चुनौती चुनाव अभियान के दौरान अपनों के बीच समन्वय व समझ बनाये रखनन की है तो जनमानस को प्रभावित करने की रहेगी तो मोल-तोल के बोल पर भी अधिक ध्यान देना होगा।

चंदा देने वाला अपने निहितार्थ देखता है और यही कारण है कि वह सत्तारुढ़ दल को अधिक चंदा देता है। इसलिए जिस तरह से यह बड़ा मुद्दा बनने की संभावना देखी जा रही थी वह सिरे नहीं चढ़ पाया। इसी तरह से केजरीवाल सहित आप नेताओं पर ईडी छापों और जेल का मुद्दा भी अधिक असर दिखाता नहीं लग रहा। इसका कारण भी साफ है कि केजरीवाल जो भ्रष्टाचार के खिलाफ ही सत्ता में आये थे पहली बात तो उनके नेताओं पर शराब ठेकों में भ्रष्टाचार के आरोप लगे, दूसरी और बार-बार सम्मन आने पर भी रेस्पांस नहीं करने और गिरफ्तारी के बाद भी पद पर बने रहने का आमजन में अभी तो नकारात्मक असर ही दिखाई दे रहा है। इस मामलें में लोग लालू की बड़ाई करने लगे हैं कि लालू ने गिरफ्तार होते ही अपना पद त्याग दिया और भले ही राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया पर पद की गरिमा को तो बनाये रखा। केजरीवाल द्वारा बार-बार सम्मन की अवहेलना करने और त्यागपत्र नही देने से लोगों में केजरीवाल के पद लोलुपता का संदेश गया अन्यथा निश्चित रुप से केजरीवाल के प्रति सहानुभूति होती और इसका लाभ समस्त विपक्ष को मिलता पर लगता है एक अच्छा अवसर खो दिया गया है। अब सवाल महंगाई को लेकर आता है तो महंगाई किसी जमाने में अपना असर दिखाती थी और प्याज के भाव बढ़ने के कारण सरकार को जाते हुए हमनें देखा है पर लगता है अब यह मुद्दा भी कुंद पड़ता जा रहा है। इसका कारण है बेरोजगारी और मंहगाई को जिस तरह से विप़क्ष को चुनावी इशु बनाना चाहिए था उसमें वह सफल नहीं हो पा रही हैं। इस चुनाव में किसानों का मुद्दा तो अभी तक दिखाई ही नहीं दे रहा।

साफ है कि 18 वीं लोकसभा के चुनाव प्रचार अभियान में संवैधानिक संस्थाओं के उपयोग, चुनाव बॉण्ड, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार आदि मुद्दें अधिक चलने वाले नहीं हैं। राम मंदिर, धारा 370 या इसी तरह के अन्य मुद्दों को विपक्ष उठाता भी है तो इसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को ही मिलेगा। ऐसे में विपक्ष को चुनावी वैतरणी पार करने के लिए कोई ठोस मुद्दें खोजने होंगे। हवा हवाई या चलताउ भाषणों, आरोप प्रत्यारोपों का जमाना अब जा चुका है। विपक्ष का निशाना नरेन्द्र मोदी ही रहेंगे और इसका उजला या स्याह पक्ष यह है कि विपक्ष जितना अधिक नरेन्द्र मोदी के नाम का उच्चारण करेगा उसका उतना ही अधिक लाभ नरेन्द्र मोदी और भाजपा को मिलेगा। ऐसे में विपक्ष को रणनीति में बदलाव करना होगा।

दरअसल विपक्ष को सकारात्मक रणनीति बनानी होगी अन्यथा नकारात्मकता को तो नरेन्द्र मोदी को अपने पक्ष में भुनाने में महारत हासिल हैं। लोक सभा के पिछले दो चुनाव और गत दस सालों के विधानसभाओं के चुनावों के परिणाम सबके सामने हैं ऐसे में विपक्ष के सामने सबसे बड़ी चुनौती भाजपा को घेरने की है और इसके लिए उसे पूर्व अनुभवों को ध्यान में रखते हुए प्रभावी रणनीति बनानी होगी। रैलियों, सभाओं में प्रमुख नेताओं को भाषणों-वक्तव्यों के दौरान सावधानी बरतनी होगी तभी मोदी जी से पार पाया जा सकता है। मोदी जी विपक्षी नेताओं द्वारा कही गई बात को तत्काल अपने पक्ष में भुनाने में सिद्धहस्त है, ऐसे में विपक्ष के सामने प्रमुख चुनौती चुनाव अभियान के दौरान अपनों के बीच समन्वय व समझ बनाये रखनन की है तो जनमानस को प्रभावित करने की रहेगी तो मोल-तोल के बोल पर भी अधिक ध्यान देना होगा। चुनाव घोषणा पत्रों में मुफ्त की सुविधाओं की भरमार अब लोगों को अधिक लुभाने वाली नहीं लगती। कारण साफ है इससे एक और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कर देने वाला अपने को ठगा समझने लगा है, वहीं लाभार्थी इसे राजनीतिक दलों की कमजोरी समझने लगा है। सौ बातों की बात यह है कि चुनाव अभियान के दौरान वक्ताओं को सोच समझ कर बोलना होगा ताकि कोई भी पक्ष अर्थ का अनर्थ ना हो सके।

–अतिथि सम्पादक,
डॉ.राजेन्द्र प्रसाद शर्मा
(वरिष्ठ लेखक)

इलैक्ट्रोरल बॉण्ड्स का मायाजाल

महावीर सिंह

इलेक्ट्रोल बांड्स और पार्टियों के चन्दे-धंदे का मायाजाल

दो आम आदमी गांव की चाय की दुकान पर चाय पर चुस्की लेते हुए इलेक्ट्रोल बांड्स पर चर्चा में उलझे हुए थे। घुमक्कड़ भी उनकी बातों में रुचि लेकर रुक गए।

एक बोला, क्यों भाई, यह ईलेक्ट्रोल बांड्स का झमेला कुछ समझ में आया क्या? अरे नहीं भैया, बड़े-बड़े धुरन्दरों के समझ में नहीं आ रहा, अपने क्या समझ में आएगा। देखो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला तो बड़ा ही किया है। यह साफ हो गया कि किस को कितना पैसा किस सेठ या धंदेबाज नें दिया है।

लेकिन यह बताओ, यह बड़े-बड़े उद्योगपति, व्यापार वाले लोग और वो भी जो इस श्रेणी में दूर-दूर तक नही, वे इतना पैसा कहां से लाकर, इन पार्टी वालों देते है और क्यों देते है?

दूसरे ने कहा, बात में दम है, जिसका व्यापार कोई खास नफे में नहीं वे भी सैंकड़ो करोड़ चंदा दे सकते है, यह बात अपनी मोटी बुद्धि में तो नहीं बैठती।

एक कुछ ज्यादा पढा-लिखा सा बंदा भी चाय का ऑर्डर देकर उनकी चर्चा में शामिल हो गया। उसने कहा देखो एक सट्टेबाज भी हजार-पांच सौ करोड़ का चंदा दे देता है और वह भी जिसकी हिसाब की किताबें इस राशि का सौवाँ हिस्सा भी लाभ नहीं दिखा रही।

उनकी चर्चा रुचिकर होती जा रही थी– इसमें चौथा भी जुड़ गया। उसके तो यही नहीं समझ में आ रहा था कि आखिर यह बड़े सेठ लोग इन मुफ्तखोर पार्टियों को इतना चंदा देते ही क्यों है?

उनमें से ही एक ने कहा, साफ है या तो व्यापार में कोई बड़ी रियायत लेंगे या व्यापार फैलाने की कोई योजना स्वीकार करवाएँगे, कोई हजारों करोड़ों का ठेका ले लेंगे और यह सब, जो चंदा देंगे उसका सो गुना कमा लेंगे। यह भी हो सकता है कि कोई बड़ा घपला कर रखा होगा, सो उसे दबाने या उस से बाहर निकलने का रास्ता बनाया होगा।

उनमें से एक नें कहा 5, 4 दिन पहले वह बस में यात्रा कर रहा था और एक अखबार, टीवी का पत्रकार सा लगने वाला आदमी बता रहा था:-

बहुत से बड़े लोगों का पैसा बाहर देशों में होता है। यह काला धन होता है क्योंकि देश के भीतर किसी बही खाते में उसका हिसाब नहीं होता। देश में ही कुछ लोग ऐसी अंडा कम्पनियां बना लेते है जिनके पास नाममात्र का धन्दा होता है। बड़े धंदे वाले लोग, अपने ऐसे दो नम्बर के या काले धन को इन कम्पनियों में भेजते है, और ऐसी कम्पनियों से बांड खरीदवा देते है। इस प्रकार जिन कम्पनियों के धन्दा मंदा है या है ही नही, वे भी राजनीतिक पार्टियों को सैंकड़ो करोड़ के बांड खरीद कर दान दाता बन सकती है।

साथ वाले ने पुछ लिया कि इनको तो ईडी, सीबीआई, इनकमटैक्स वाले बड़ी आसानी से कभी भी पकड़ सकते है। यह सब संस्थाएँ सरकारों के इशारे पर ऐसे काम करती है। पत्रकारनुमा आदमी ने कहा– बताओ, कोई सोने के अंडे देने वाली मुर्गियों को मारता है क्या? दान में मिली बछिया के दांत कोई गिनता है क्या? बस यह ऐसा ही मिलीजुली का खेल है।

एक ने चर्चा को नया मोड़ दिया--कुछ भी हो, एक बड़ी पार्टी का कहना है कि पहले तो, अधिकतर खुल्लमखुल्ला ही काला धन चुनावी चंदे में चलता था किंतु अब किसी भी रास्ते से हो,चंदे में सफेद धन ही मिल रहा है। काले धन से राजनीति करने वालों की दुकाने बन्द।

उनमें से फिर कोई बोला---दिल को तसल्ली देने के लिए ख्याल अच्छा है। अरे मेरे भोले भाई, यह बांड्स से मिले 10, 20 हजार करोड़ रुपए से ही पार्टियों के बड़े नेता महाराजों जैसी जिंदगी जी ढकते हैं क्या? क्या इतने से पैसे से चुनाव लड़ लिए जाते हैं क्या?

कुछ बड़े दानिशमंद लोगों का कयास है कि भारत के लोकसभा चुनाव में कम से कम एक लाख करोड़ रु से कम खर्च नही होता। इसका 70, 80 प्रतिशत तो काले धन के रास्ते ही आता है। इस से भी अधिक, हमारे महान लोकतांत्रिक देश में तो हर साल छ महीने चुनाव चलते ही रहते है, उनके लिए भी पैसा चाहिए। सरकारें बनाने-बिगाड़ने के लिए भी तो टनों पैसे की जरूरत पड़ती है--साथ वालों को खुश करने में, दूसरी तरफ वालों को ललचाने के लिए!!!

किसी दूसरे ने भी प्रश्न किया--यह ईडी, सीबीआई, आईटी विभागों के द्वारा, राज्यों के विभागों के द्वारा सर्च-रेड आदि करने के बाद कुछ कम्पनियों नें चंद दिया, बांड्स खरीद कर। यह क्या बात हुई, यह तो सीधे-सीधे सरकारों के द्वारा जबरन उगाही हुई न?? ऐसे लोगों ने जो पार्टी सरकार में बैठी है उसके साथ विपक्षियों को भी बांड्स से चंदा दिया है--क्यों? यह बात कुछ समझ से परे है?

किसी ने यों ही थोड़ी अलग बात उछाल दी कि यह समझाओ सरकार कहीं की हो, किसी दल की हो, सारे भ्रष्टाचारी, विपक्षियों में ही क्यों दिखते है?? क्या सत्ता पक्ष वाले सारे रामजी महाराज के नए अवतार हैं???

पहले वाले नें, बातों का पुराना सिलसिला आगे बढाते हुए समझाया--सरकारी पक्ष को ज्यादा दे दिया, सो वे खुश--कमजोर विपक्ष वालों को कुछ भी कुछ दे दिया, इस से आगे के रास्ते खुले रहते है। देने वाला जनता है सत्ता पर किसी एक ही पार्टी की बपौती थोड़े ही न है,जनता कब पलटा मार ले कोउ न जानत। वो एक पुराना दोहा है न---पुरुष पुरातन की--- (सत्ता) क्यों न चंचला हो---।

तो फिर, यह रैलियों, सभाओं में नेताओं की गर्जन-तर्जन यों ही है कि नोट बंदी से काला धन समाप्त, बाहर जितना पैसा था वह सब देश में आ गया भ्रष्टाचारयो की दुकान बंद, उनका घर जेल। ओर क्या ऐसा सारा कला धन देश में व्यापार, उद्योग में लग गया जिस से लाखों न लाखों को रोजगार मिल गया?

फिर एक ने कहा, यह सब नारे, तमाशे है और इन तमाशों के बल पर ही वोटों की फसल काटी जाती है। आगे नई लूट के रास्ते बनाए जाते है। कोउ पार्टी दूध की धुली नहीं, हमाम में सब के सब नंगे है। हॉ, जो पार्टी बड़े पैमाने पर तमाशे दिखाएगी, जनता उस पर लटटू हो जाए, इसकी संभावनाएं ज्यादा है।

बातों को विराम देते हुए दूसरे नें कहा, देख भाई, इन बातों में अपने लिए कुछ नहीं रखा। अपने को तो छोटे वाले नेताओं के साथ रैलियों में जाना है, तमाशा देखना। हो सकता है दिहाड़ी मिल जाए वरना मुफ्त बस यात्रा और पूरियों के पैकेट में कोउ कमी नहीं। नेता लोग, वोट पड़ने तक फ्री खाने के ढाबे चलाते है खाना खाओ, मोज करो। कुछ कुछ के लिए पीने की भी व्यवस्था करते है, पीओ और नारे लगाते रहो!!!

भाई लोगो, वोट वाले दिन वोट जरूर डालना और सोच समझ कर डालना। हो सके तो यह भूल जाना कि ज्यादा मुफ्त बस यात्रा किसने करवाई, पूरियों के पैकेट किसने दिए, तमाशे किस के ज्यादा मनोरंजक थे, जहां आपका जमीर आपके वर्ग हित पूरे होने की ज्यादा सम्भवनाओं का इशारा करे उसको ही वोट डालना। ''नेताओं, सेठों, उद्योगपतियों की तो वे जानें किन्तु आम आदमी के हक हकूक तो संविधान से ही है और उस से ही सुरक्षित है, रहेंगे''

''इस लिए जय संविधान, जय लोकतंत्र--यही देश की विश्व में सही पहचान''।

महावीर सिंह,
पूर्व आईएएस

विश्व आवारा पशु दिवस पर विशेष

पशु कल्याण के प्रति सच्ची करुणा हो

मरियम अबु हैदरी

भारत की हलचल भरी सड़कों पर, दैनिक जीवन की उथल-पुथल के बीच, एक मूक पीड़ा मौजूद है जिस पर अक्सर ध्यान नहीं जाता है - आवारा जानवरों की दुर्दशा। जबकि विश्व आवारा पशु दिवस उनके संघर्षों की मार्मिक याद दिलाता है, यह पहचानना आवश्यक है कि यह मुद्दा जागरूकता के एक दिन से अधिक का है। यह एक व्यापक, जारी संकट है जो समाज के सभी क्षेत्रों से तत्काल ध्यान देने और ठोस कार्रवाई की मांग करता है। जैसे-जैसे हम अपने शहरों की भूलभुलैया वाली गलियों और हलचल भरी सड़कों पर घूमते हैं, आवारा कुत्तों, बिल्लियों, गायों और असंख्य अन्य जानवरों की उपस्थिति को नजरअंदाज करना असंभव है जो हमारी सड़कों पर भोजन और आश्रय की तलाश में घूमते हैं। फिर भी, उनकी प्रतीत होने वाली अहानिकर उपस्थिति के पीछे उपेक्षा, दुर्व्यवहार और उदासीनता की एक कठोर वास्तविकता छिपी हुई है।

इस संकट की जड़ सामाजिक-आर्थिक कारकों, विधायी कमियों और जानवरों के प्रति मीडिया-प्रेरित दृष्टिकोण के जटिल जाल में निहित है। पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 जैसे कानून के अस्तित्व के बावजूद, जिसका उद्देश्य स्पष्ट रूप से जानवरों के कल्याण की रक्षा करना है, प्रवर्तन तंत्र बेहद अपर्याप्त हैं। छह दशकों से अधिक समय से, कानून का यह महत्वपूर्ण हिस्सा अधर में लटका हुआ है, नौकरशाही जड़ता और राजनीतिक उदासीनता के कारण सकारात्मक बदलाव लाने की इसकी क्षमता बाधित है।

इस विश्व आवारा पशु दिवस पर, एक कड़वी सच्चाई को स्वीकार करना अनिवार्य है: भारत में आवारा जानवरों की दुर्दशा सिर्फ कुत्तों से भी आगे तक फैली हुई है। इस खेदजनक स्थिति में विभिन्न प्रजातियाँ शामिल हैं, जो एक प्रणालीगत विफलता को उजागर करती है जिस पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। हिंदू धर्म में जानवरों से जुड़े गहरे सांस्कृतिक महत्व को देखते हुए, कोई उम्मीद करेगा कि भारत अहिंसा की भूमि के रूप में अपनी प्रतिष्ठा की सुरक्षा को प्राथमिकता देगा। किसी तरह पशु कल्याण उपायों का चयनात्मक अनुप्रयोग भारतीय समाज के भीतर एक परेशान करने वाले पाखंड को रेखांकित करता है। नसबंदी के प्रति हमारा चयनात्मक दृष्टिकोण एक गहरे पाखंड को रेखांकित करता है। रेबीज के कथित खतरे के कारण हम कुत्तों और बिल्लियों को प्राथमिकता देते हैं, फिर भी दूध उत्पादन की आड़ में गायों के शोषण पर आंखें मूंद लेते हैं। हमारी पाठ्यपुस्तकों में इस धारणा को चुनौती दी जानी चाहिए कि 'गायें हमें दूध देती हैं'।

वास्तविकता स्पष्ट है: सबसे जघन्य दुर्व्यवहार गायों के बीच होता है, जिन्हें पवित्र माना जाता है फिर भी हिंसा के जघन्य कृत्यों का सामना करना पड़ता है। नर बछड़ों को त्याग दिया जाता है या मार दिया जाता है, जबकि जानवरों की स्वायत्तता की परवाह किए बिना आक्रामक कृत्रिम गर्भाधान को मंजूरी दे दी जाती है। इन प्रथाओं में हमारी सरकार की मिलीभगत निंदनीय है, फिर भी 'कुत्ते के काटने' और 'कुत्ते के आतंक' जैसी अधिक सनसनीखेज खबरों के शोर के बीच इसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है।

संसद के भीतर पशु अधिकारों की वकालत करने वाली मेनका गांधी जैसी उल्लेखनीय शख्सियतों और जॉन अब्राहम जैसी मशहूर हस्तियों द्वारा 'नो मोर 50' अभियान जैसी पहल किए जाने के बावजूद निष्क्रियता देखना हैरान करने वाला है। क्या यह सब केवल प्रतीकात्मक है, ठोस कार्रवाई के बिना चिंता का दिखावा है? और कुत्तों के लिए पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रम के बारे में क्या? शुरुआत में जनसंख्या नियंत्रण के उद्देश्य से की गई नसबंदी की विधियां जानवरों की कीमत पर व्यक्तियों को लाभ पहुंचाने वाली पैसा कमाने वाली योजनाओं में बदल गई हैं। यह भ्रष्टाचार उच्चतम स्तर से लेकर बहुत नीचे तक व्याप्त है, व्यक्तिगत लाभ के लिए निर्दोष जानवरों का चारे के रूप में शोषण करता है। अंतर्निहित मुद्दा कानून से परे फैला हुआ है - यह राजनीतिक इच्छाशक्ति और नैतिक अखंडता का मामला है। पशुपालन जैसे विभागों में प्रमुख पदों पर नियुक्त व्यक्तियों को पशु कल्याण को संबोधित करने के लिए अपर्याप्त रूप से सुसज्जित क्यों किया जाता है? उन लोगों की आवाज़ कहाँ है जो जानवरों को समझते हैं और उनके प्रति सहानुभूति रखते हैं, नीति निर्धारण क्षेत्रों में उनके अधिकारों की वकालत करते हैं?

डेयरी उद्योग के भीतर प्रणालीगत भ्रष्टाचार के बजाय छिटपुट घटनाओं पर ध्यान केंद्रित करने से मीडिया की आत्मसंतुष्टि इस मुद्दे को और बढ़ा देती है। अवैध डेयरियाँ बेधड़क चल रही हैं, सार्वजनिक स्वास्थ्य को खतरे में डाल रही हैं और लाभ के लिए जानवरों का शोषण कर रही हैं। दुरुपयोग के इस चक्र को जारी रखने में उनकी भूमिका के लिए सरकारी एजेंसियों और निर्वाचित राजनेताओं और गौशालाओं दोनों को जवाबदेह बनाने का समय आ गया है।

जैसा कि शाहरुख खान ने फिल्म 'जवान' में स्पष्ट रूप से व्यक्त किया है, हमें उन लोगों की जांच करनी चाहिए जिन्हें हम सत्ता सौंपते हैं, उनके कार्यों में जवाबदेही और पारदर्शिता की मांग करते हैं। हमारे नेताओं की उदासीनता ऐसे अत्याचारों को जारी रखने में सक्षम बनाती है, जबकि जनता उनकी चुप्पी में निश्चिंत रहती है।

इन बहुआयामी चुनौतियों से निपटने के लिए, हमें वन हेल्थ के सिद्धांतों द्वारा सूचित एक व्यापक, अंत:विषय दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। वन हेल्थ दृष्टिकोण का एक प्रमुख पहलू विधायी सुधार की वकालत करना है जो पशु अधिकारों और कल्याण की समकालीन समझ को दर्शाता है। अपनी सामूहिक आवाज़ों का लाभ उठाकर और नीति निर्माताओं को जवाबदेह बनाकर, हम पुराने कानूनों में बहुत आवश्यक संशोधनों को आगे बढ़ा सकते हैं और उनके मजबूत प्रवर्तन और सरकारी नीति के रूप में कृत्रिम गर्भाधान को हटाने को सुनिश्चित कर सकते हैं।

इसके अलावा, जिम्मेदार पालतू स्वामित्व को बढ़ावा देना और बधियाकरण और बधियाकरण कार्यक्रमों जैसी सहायक पहल वन हेल्थ रणनीति के महत्वपूर्ण घटक हैं। पशु कृषि में स्थायी प्रथाओं को अपनाना और वाणिज्यिक उद्यमों में जानवरों के नैतिक उपचार की वकालत करना वन हेल्थ प्रतिमान का अभिन्न अंग है। पर्यावरण संरक्षण और सार्वजनिक स्वास्थ्य के साथ-साथ पशु कल्याण को प्राथमिकता देकर, हम सभी के लिए अधिक न्यायसंगत और टिकाऊ भविष्य बना सकते हैं।

इसके अतिरिक्त, सभी जीवित प्राणियों के प्रति करुणा की संस्कृति विकसित करने के लिए समुदायों के भीतर सहानुभूति और जागरूकता को बढ़ावा देना आवश्यक है। ऐसे कई ठोस कदम हैं जिन्हें व्यक्ति बदलाव लाने के लिए उठा सकते हैं: पश्चिम से सीखें: हम सांस्कृतिक मतभेदों के बावजूद जानवरों के प्रति पश्चिमी देशों की दयालु नीतियों से प्रेरणा ले सकते हैं। कई देशों ने गोद लेने के लिए प्रोत्साहन देकर और जानवरों की बिक्री पर जुर्माना लगाकर, गोद लेने के लिए कर लाभ की पेशकश करते हुए खरीद पर भारी कर लागू करके आवारा जानवरों की समस्याओं को सफलतापूर्वक संबोधित किया है। उदाहरण के लिए, तुर्की सामुदायिक जानवरों के साथ सह-अस्तित्व का उदाहरण देता है, सड़कों पर आवारा बिल्लियों और कुत्तों के लिए घर और भोजन की व्यवस्था प्रदान करता है। यदि तुर्क और नीदरलैंड जैसे देश इसे प्रबंधित कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं? उनके स्वच्छ और अच्छी तरह से निर्मित पशु आश्रय स्थल, दयालु पशु चिकित्सकों से सुसज्जित, जिन्होंने स्वेच्छा से अपना पेशा चुना, एक स्पष्ट विरोधाभास को उजागर करते हैं। पशु चिकित्सा लापरवाही को सख्ती से संबोधित किया जाता है, और वे वर्दीधारी पेशेवरों के साथ स्वच्छता मानकों को बनाए रखते हुए, पशुधन सहायकों पर पशु चिकित्सा नर्सों को प्राथमिकता देते हैं।

विधायी सुधार के पक्षधर: निर्वाचित प्रतिनिधियों से पशु कल्याण कानून को प्राथमिकता देने और विरोध प्रदर्शन और लगातार बैठकें आयोजित करके इसका जोरदार कार्यान्वयन सुनिश्चित करने का आग्रह करें। पशु अधिकारों और कल्याण के आधुनिक मानकों के अनुरूप पशु क्रूरता निवारण अधिनियम जैसे पुराने कानूनों में संशोधन की वकालत करना। भले ही पिछले प्रयासों, जैसे कि मेनका गांधी के नेतृत्व में, तत्काल परिणाम नहीं देते थे, यह आवश्यक है कि आशा न खोएं - शायद प्रयास के लिए अधिक दृढ़ दृढ़ता की आवश्यकता होती है। जिम्मेदार गैर सरकारी संगठनों का समर्थन करें: प्रतिष्ठित गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) की पहचान करें और उनका समर्थन करें जो सक्रिय रूप से पशु बचाव, पुनर्वास और वकालत में लगे हुए हैं। स्वेच्छा से समय देकर, संसाधन दान करके, या सोशल मीडिया पर अपना संदेश फैलाकर, व्यक्ति पशु कल्याण के लिए व्यापक आंदोलन में योगदान दे सकते हैं।

दयालु प्रथाओं को बढ़ावा दें: समुदायों को जानवरों के लिए मानवीय उपचार प्रथाओं के बारे में शिक्षित करें, जिसमें अधिक जनसंख्या को रोकने के लिए पालतू जानवरों को बधिया करने और बधिया करने का महत्व भी शामिल है। जिम्मेदार पालतू पशु स्वामित्व को प्रोत्साहित करें और क्रूरता और शोषण को कायम रखने वाली प्रथाओं को हतोत्साहित करें।

सहानुभूति और जागरूकता को बढ़ावा: आवारा जानवरों की दुर्दशा और उनकी पीड़ा को बनाए रखने वाले प्रणालीगत मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया, होर्डिंग, सामुदायिक मंच और शैक्षिक पहल जैसे प्लेटफार्मों का उपयोग करें। सभी जीवित प्राणियों के प्रति करुणा की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए संवाद और सहानुभूति-निर्माण अभ्यास को प्रोत्साहित करें।

अधिकारियों को जवाबदेह ठहराएं: सरकारी एजेंसियों को पशु कल्याण के मुद्दों को संबोधित करने में उनकी भूमिका के लिए जिम्मेदार रखें, जिसमें नसबंदी कार्यक्रमों और श्मशान के लिए संसाधनों का आवंटन, क्रूरता विरोधी कानूनों को लागू करना और जानवरों का शोषण करने वाले वाणिज्यिक उद्यमों का विनियमन शामिल है। नगर निगमों, पुलिस और अपने स्थानीय विधायकों से शुरुआत करें।

गोद लें, खरीदारी न करें: वाणिज्यिक प्रजनकों से पालतू जानवर खरीदने के बजाय किसी आश्रय या बचाव संगठन से आवारा जानवर को गोद लेने पर विचार करें। किसी जरूरतमंद जानवर को एक प्यार भरा घर प्रदान करके, व्यक्ति आवारा आबादी को कम करने और पीड़ा को कम करने में सीधे योगदान दे सकते हैं।

यह पहचानना महत्वपूर्ण है कि आवारा जानवरों का कल्याण आंतरिक रूप से सामाजिक न्याय, पर्यावरणीय स्थिरता और नैतिक शासन के व्यापक मुद्दों से जुड़ा हुआ है। जानवरों के अधिकारों और सम्मान की वकालत करके, हम मानव और गैर-मानव सभी प्राणियों के लिए एक अधिक न्यायपूर्ण, दयालु समाज बनाने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हैं।

इस विश्व आवारा पशु दिवस पर, आइए हम प्रधान मंत्री मोदी और सभी राजनीतिक दलों के नेताओं से पशु कल्याण के प्रति सच्ची करुणा और प्रतिबद्धता प्रदर्शित करने का आव्हान करें। यह ठोस कार्रवाई का समय है, खोखले वादों या सांकेतिक इशारों का नहीं। हमारी सड़कों पर आवारा जानवरों की पीड़ा निर्णायक, परिवर्तनकारी परिवर्तन से कम कुछ नहीं मांगती है। अब समय आ गया है कि हमारी सरकार अपनी नींद से जागे और हमारे समुदायों को परेशान करने वाले व्यापक अन्याय का मुकाबला करे।

यह दिखाने का समय आ गया है कि भारत वास्तव में अपने सभी निवासियों की परवाह करता है, चाहे वे किसी भी प्रजाति के हों। साथ मिलकर, हम एक ऐसी दुनिया बना सकते हैं जहां मनुष्यों, जानवरों और पर्यावरण की भलाई आंतरिक रूप से जुड़ी हुई है - एक ऐसी दुनिया जहां हर जीवन, चाहे वह कितना भी छोटा या कमजोर क्यों न हो, मूल्यवान और संरक्षित है।

मरियम अबु हैदरी,
वन्य जीव प्रेमी

राशिफल

पंडित अनिल शर्मा

गुरूवार 4 अप्रेल, 2024

चैत्र मास, कृष्ण पक्ष, दशमी तिथि, गुरूवार, विक्रम संवत 2080, श्रवण नक्षत्र रात्रि 8:12 तक, सिद्ध योग दिन 11:15 तक, विष्टि करण सांय 4:15 तक, चन्द्रमा मकर राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति: सूर्य-मीन, चन्द्रमा-मकर, मंगल-कुम्भ, बुध-मीन, गुरू-मेष, शुक्र-मीन, शनि-कुम्भ, राहु-मीन, केतु-कन्या राशि में।

आज भद्रा सांय 4:15 तक है। आज दशामाता व्रत है।

श्रेष्ठ चौघड़िया: शुभ सूर्योदय से 7:51 तक, चर 10:57 से 12:30 तक, लाभ-अमृत 12:30 से 3:26 तक, शुभ 5:09 सूर्यास्त तक।

राहूकाल: 1:30 से 3:00 तक। सूर्योदय 6:18, सूर्यास्त 6:42

मेष
व्यावसायिक कार्यों पर ध्यान देना ठीक रहेगा। व्यावसायिक कार्य शीघ्रता से बनने लगेंगे। महत्वपूर्ण कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी।

वृष
नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। व्यावसायिक कार्यों में व्यस्तता अभी यथावत बनी रहेगी। धार्मिक कार्यों पर धन खर्च हो सकता है।

**मिथ